

(ii) निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र :-

⇒ विकास के दोनो मॉडल पूँजीवादी व समाजवादी मॉडल को ध्यान में रखते हुए ली लिया गया तथा भारत में इन्हे मिले-जुल्ले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।

⇒ मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना द्विधरणपंथी तथा वामपंथी दोनों वर्गों ने की। उनका कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान नहीं दिया तथा न ही निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किया।

⇒ कुछ आलोचकों का मत था कि सरकार को जितना करना चाहिए था, उतना उसने नहीं किया। जनता की शिक्षा या चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ धनराशि खर्च नहीं की।

(5) मुख्य परिणाम :-

⇒ नियोजित विकास के प्रारम्भिक प्रयासों के देश के आर्थिक विकास और समस्त नागरिकों की भा भाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता प्राप्त हुई। प्रारम्भिक दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आई।

(i) बुनियाद :-

⇒ नियोजित विकास के इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएँ इसी अवधि में प्रारम्भ हुईं, जैसे - आखड़ा - नांगल परियोजना व

⇒ सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग, जैसे - इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माण इकाइयाँ, रक्षा - उपादन आदि सभी अवधि में प्रारम्भ हुए ।

(ii) भूमि सुधार :-

⇒ इस अवधि में भूमि सुधार के शीघ्र प्रयास हुए जैसे - जमींदारी प्रथा की समाप्ति । कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम रख सकता है । काश्तकारों को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई,

(iii) खाद्य संकट :-

⇒ सन् 1960 के दशक में कृषि की दृशा अत्यन्त सोचनीय हो गयी । बिहार में खाद्यान्न संकट बढ़ने से यहाँ की स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गयी थी । बिहार के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का अभाव उत्पन्न हो गया था ।

(iv) हरित क्रांति :-

⇒ खाद्यान्न के इस संकट से देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गयी थी । संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य सहायता देने के लिए भारत को आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला ।

⇒ सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई ।